University Grants Commission, New Delhi Recognized Journal No. 41311
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

उत्तराखण्ड में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 की भूमिका का अध्ययन

कर्ण सिंह

सहायक प्रोफेसर ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, काशीपुर, उत्तराखंड

देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के मकसद से अलग-अलग समय पर अनेकों तरह की योजनाओं को सरकार द्वारा अमलीजामा पहनाया गया है। उसमें से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 है, जो 24x7 सेवा है जो लोगों के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने में अपना योगदान देती है, समय समय पर अनेकों राज्य ने इस योजना का अपने राज्य में लागू किया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य ने अपनी स्थापना के गठन के 8 साल बाद इस आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 योजना को अपने यहां लागू किया गया था। गौरतलब है कि चौबीसों घंटे सुविधाओं का दम भरने वाली इस सुविधा का पहाड़ी प्रदेश में कितना फायदा हो पाया है यह विचारनीय होगा। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों ने अलग- अलग मापदण्डों के तहत इस सुविधा को अपने यहां लागू किया है। यह प्रदेश है - आँध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, तामिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, असम, मेघालय और मध्य प्रदेश। उत्तराखण्ड राज्य में मई 2008 में इस एम्बुलेंस सेवा ने पहली बार अपनी उड़ान भरी थी जिसके बाद शुरूआती दौर में इसको पहाड़ों प्रदेश की लाईफलाइन में अहम किरदार निभाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यह सेवा 11 लाख से ज्यादा लोगों की आपातकालीन मददगार एवम् जीवनदायिनी साबित हो चुकी है। वहीं इस खुशियों की सवारी 108 ने 10 हजार से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने का गौरव अपने नाम किया है। वर्तमान में यह सेवा बंद हो चुकी है इसके कारणों को समझते हुए इस शोध पत्र में यह जानने की कोशिश की जाएगी बीते दस सालों में इस सुविधा का लाभ आमजन कैसे उठा पाए है।

मुख्य शब्द- 108, स्वास्थ्य सुविधा, आपातकाली सेवा, पहाड़ी क्षेत्र

प्रस्तावना- हम सभी को ज्ञातव्य है कि उत्तर-भारत के स्थित उत्तराखंड राज्य का गठन साल 2000 में काफी अथक प्रयासों के बाद हुआ था। भारत गणराज्य का 27वें राज्य का गौरव हासिल कर इस प्रदेश को उत्तरांचल के नाम से जाना जाने लगा था। वहीं साल 2007 में इस प्रदेश की भावनाओं को ध्यान में रखकर इसका आधिकारिक नाम उत्तराखण्ड कर दिया गया था। यह भी गौरतलब है कि किसी राज्य से अलग होने पर उस राज्य की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अन्य सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र के रहवासियों को तमाम सुविधा मुहैया कराए। इस कड़ी में स्वास्थ्य प्रबंधन का उचित मापदंड आम लोगों को उपलब्ध कराना भी उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। दरअसल हर सरकार को अपने राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति एवम् राज्य में मौजूद तमाम लोगों के जीवन स्तर में सुधार जैसे तमाम मुद्दों पर हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

हम सब जानते है कि उत्तराखड राज्य एक पहाड़ी राज्य है जहां पर जीवन व्यापन की परिस्थिति ओर भी मुश्किल से भरी होती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में चिकित्सा विभाग के लिए हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना किसी चैलेंज और जोखिम से कम नहीं है। भले ही प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, लेकिन चिकित्सकों और बेहतर सुविधा के अभाव में यह केंद्र केवल शोपीस बने नज़र आ रहे है। स्थिति यह है कि प्रदेश में अभी लगभग आधे से ज्यादा पद रिक्त है जिसका मुख्य कारण भारी भरकम पैकेज की मांग भी है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में आपात स्थिति में स्वास्थ्य से जुड़ी प्राथमिक सुविधा मिल

पाना दुर्लभ है वहां पर हेली एंबुलेंस का सपना देखना एक मुंगेरी लाल के सपनों जैसा ही सिद्द होगा।

आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 का उदय- जीवीके फाउंडेशन की शुरूआत हैदराबाद के डॉ गनूपति वेंकट कृष्णा रेड्डी(Gunupati Venkata Krishna Reddy) के द्वारा की गई है। इसके जरिये जीवीके संस्थान सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। दरअसल जीवीके एक सोशल एक्टिविटी विंग है जो राष्ट्रीय स्तर पर कई विकास कार्यक्रम चलाता है जैसे कि निम्न स्तर के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, समुदाय आधारित कार्यक्रम, सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास, कला, संगीत, खेल, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ कई अन्य तरह के सामाजिक-आर्थिक पहल इसमें शामिल है। [i]यह जीवीके ईएमआरआई (आपातकालीन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान) जीवीके द्वारा संचालित सभी पहलों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो पीपीपी मॉडल(पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) पर काम कर रहा है। जिसमें देश की हर आपातकालीन स्थिति को शामिल किया गया है जैसे चिकित्सा संकट, कानून और व्यवस्था की स्थिति या आग आपदा आदि। यह विश्व स्तर के हिसाब से राष्ट्र की सेवा में आधुनिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी सेवा प्रदान करती है। अगर हम ईएमआरआई(इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट) के इतिहास पर गौर देगें तो यह पता चलता है कि इसका प्रारंभ सत्यम कंप्यूटर्स ने की थी। लेकिन जनवरी 2009 में सत्यम् कंप्यूटर्स आर्थिक घोटाले में फंस गया, जिसके बाद ईएमआरआई को जीवीके कंपनी ने खरीद लिया था।

देश में चिकित्सा संकट को ध्यान में रखते हुए सन् 2005 से आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 की शुरूआत की गई थी जो सबसे पहले आंध्रप्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। वर्तमान में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 देश के 15 राज्यों - आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल के अलावा दो केंद्र शासित प्रदेशों दीव-दमन और दादरा नगर हवेली में 24X7 के आधार पर अपनी सेवा प्रदान कर रही है, इसकी व्यापक पहल की शुरूआत लगभग 11,000 एम्बुलेंस से लैस थी जिसने 45 मिलियन से अधिक मामलों में भाग लिया गया है और 1.5 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। इस सेवा की खास बात यह है कि 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा ने 6800 अस्पतालों से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत प्रथम 24 घंटे प्रारंभिक स्थिरीकरण (इलाज) मुफ्त करेंगे।[ii]

राज्यवार आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 विवरण[iii]-

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	108 एंबुलेंस की संख्या	जेएसएसके ड्रॉप बैक एम्बुलेंस की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	468	279
2.	तेलंगाना	334	219
3.	गुजरात	585	262
4.	उत्तराखंड	140	98
5.	गोवा	34	4
6.	तमिलनाडु	839	-
7.	कर्नाटक	754	-
8.	असम	701	235
9.	मेघालय	48	-

10.	मध्य प्रदेश	624	-
11.	हिमाचल प्रदेश	198	126
12.	छत्तीसगढ़	238	362
13.	उत्तर प्रदेश	1488	2270
14.	राजस्थान	638	586
15.	श्रीलंका	88	-
16.	दीव-दमन और दादरा नगर हवेली	17	-

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	जनवरी 18 के अनुसार जननी एम्बुलेंस की संख्या	स्थापना के बाद से जननी लाभार्थी	जननी लाभार्थी जनवरी 18 तक
1.	असम	235	14,48,587	17,979
2.	उत्तराखंड	90	4,23,493	1,809
3.	गुजरात	248	21,54,645	42,444
4	आंध्रप्रदेश	279	6,80,488	25,000
5	तेलंगाना	241	4,25,586	42,315
6	छत्तीसगढ़	362	30,27,679	54,730
7	उत्तर प्रदेश	2,270	3,10,73,305	6,34,710
8	हिमाचल प्रदेश	126	1,80,741	3,321
9	गोवा	2	5,364	31
10	राजस्थान	587	22,40,986	76,203
11	पश्चिम बंगाल	650	2,61,187	49,278

*** http://www.emri.in/ से साभार**

उत्तराखण्ड में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 की शुरूआत- देश में चिकित्सीय सुधारों को लेकर पीपीपी मॉडल पर आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 का आरंभ देवभूमि उत्तराखण्ड में सन् 2008 से हुई थी। इस सेवा के प्रदेश में आरंभ होने से वर्तमान तक सेवाएं देने का ब्यौरा निम्नलिखित है-

उत्तराखण्ड राज्य में सेवाएं प्रदान करने की स्थिति[iv]

आपात स्थिति में सेवा दी- 12,84,482

जीवन बचाएं- 31,477

प्रसूताओं में सहायता- 13,877

इस सब आकड़ों के इतर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक दृष्टि से एक पर्वतीय राज्य है। जहां रहन-सहन को लेकर आए दिन नई- नई मुश्किलों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दुर्गम पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि वहां पर सड़क मार्गों की हालत खस्ताहाल रहती है।[v] ऐसे में प्रत्येक नागरिक तक आम जन सुविधा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण तो होता ही साथ ही अनहोनी

की संभावना भी बहुत होती है। ऐसे क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 108 को लागू करना जीवीके संस्थान और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था।

108 एंबुलेंस के मानक और हकीकत में विरोधाभास की स्थिति- WHO यानि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंबुलेंस वाहनों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइड़लाइनों के अनुसार एंबुलेंस को डेढ़ लाख किलोमीटर या अधिकतम तीन साल तक संचालन किया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य इस गाइडलाइनों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, प्रदेश में मानकों के विपरित इस एंबुलेंसों का संचालन किया जा रहा है जिसमें अधिकतर वाहनों की हालत खस्ताहाल है। इन एंबुलेंसो के बाहरी संचालन में आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहां तक की अधिकतर उपकरण पुराने और खराब हो चुके है। 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा की वर्तमान हालत यह है कि सत्तर फीसदी गाडियों तीन लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। यह दीगर है कि सूबे कि लाइफलाइन कहलाने वाली सेवा ही विषम परिस्थिति के गर्त में जा चुकी है ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के लोग किसके सहारे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। [vi]

वहीं अगर कुछ रिपोर्टों के खुलासे पर नज़र डाले तो पता चलता है कि यह सेवा प्रदेश में काफी समय से बिना करार से चलती है जो शासन- प्रशासन की सुस्ती के बारे में बताती है। दूसरी तरफ कैग ने अपने परफार्मेंस ऑडिट में 108 सेवा की कई ऑडिट पर आपतियां दर्ज करवाई है। दरअसल वर्ष 2008 में सरकार ने जिस निजी संस्थान से 108 सेवा संचालन का करार किया था जिसका अभी कोई अता-पता नहीं है, 2009 से जिस कंपनी के माध्यम से सेवाएं का जैसे तैसे संचालन हुआ उसके साथ भी औपचारिक एमओयू साइन नहीं हुआ, नंवबर 2012 में किसी अखबार में मामला उजागर होने के बाद शासन के कान खड़े हो गए और इसकी जांच शुरू हो गई है कि बिना करार के कैसे यह सेवा प्रदेश में चलती रही है। वर्तमान में तो स्थिति यह कि 717 फील्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कार्य का सामूहिक बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए है।[vii]

आपको बता दें कि GVK EMRI 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा हर साल 2अप्रैल को EMT दिवस का आयोजन करती है। 2018 में आयोजित सालाना दिवस कार्यक्रम में सेवा के राज्य प्रमुख मनीष टिंकू ने EMT कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि वे 108 एम्बुलेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की टीमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे आपातकालीन सेवाएं 24x7 प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि EMT पीड़ित या मरीज को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा और उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि 108 सेवा ने अब तक 12.50 लाख मामलों को आपातकालीन सेवा प्रदान की है और उत्तराखंड में ईएमटी द्वारा 31500 लोगों की जान बचाई गई है। टिंकू ने कहा कि इन तकनीशियनों ने एंबुलेंस में 10200 महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया है। वहीं ईएमटी के कुछ लोगों ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि देश में 108 एम्बुलेंस सेवा में कुल 19200 EMT काम कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में 315 EMT सेवा उपलब्ध है।[viii]

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां- प्रदेश मे बेहतर सेवा का दम भरने वाली 108 सेवा जहां एक तरफ सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं को पटरी पर लाने में योगदान दे रहीं है , वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था आम लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। आलम यह है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय नई एंबुलेंस बीते कुछ समय से धूल खा रहीं है। वहीं महकमे में उपकरणों की खरीद पर भी सवाल उठते रहे है। पूर्व के आकडों के अनुसार एक एंबुलेंस करीब 9 लाख 77 हजार में पड़ी थी लेकिन बाद में इनकी कीमत बढ़कर 9 लाख 53 हजार हो गई है, इन स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौन है। हाल ही में नौबत यहां तक आ गई कि जीवीके प्रबंधन और फिल्ड कर्मचारी वेतन, छुट्टियों आदि अपनी मागों को लेकर आमने आमने – सामने आ गए है। जिस कारण प्रदेश में खुशियों की सवारी का संचालन ठप पड़ा है। वहीं सरकार कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद सरकार वैकल्पिक व्यवस्था का संचालन शुरू करने का प्रयास

कर रहीं है। 108 के प्रभारी मनीष टींकू ने बताया कि यूपी व हिमाचल से कुछ कर्मियों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया दैनिक व्यवस्था पर कुछ कर्मियों की व्यवस्था की गई है, साथ ही सभी जिलों में सीएमओ स्तर से कुछ कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जल्द ही 40 प्रतिशत वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।[ix]

"कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है कि जल्द काम पर लौटे वरना कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जल्द ही नए सिरे से नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी – मनीष टिंकू, प्रदेश प्रभारी, 108 सेवा

वहीं कर्मचारी संघ का कहना है कि "108 सेवा कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव विपिन जमलोकी का कहना है कि सामूहिक कार्य बहिष्कार पर कर्मचारियों के जाने की नौबत कैसे आई , यह सरकार के लिए सोचनीय विषय है। 108 सेवा मे काम करने वाले व्यक्ति भी इसी प्रदेश के लोग है, उनकी बात सुननी चाहिए, कर्मचारियों के उत्पीड़न के बावजूद सरकार कंपनी का पक्ष ले रही है। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे" – विपिन जमलोकी , प्रदेश सचिव. 108 कर्मचारी संघ

दरअसल कर्मचारी अपनी कुछ अपनी मांगों को लेकर नाराज चल रहें है-

- 14 और 15 अगस्त का काटा गया वेतन लौटाया जाए।
- प्रत्येक माह की पांच तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए।
- कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित की जाए।
- प्रबंधन कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू न करे।

जिस एजेंसी के पास संचालन का जिम्मा है , उसका अनुबंध समाप्त होने वाला है। यह मरीजों के जीवन से जुड़ा बिंदु है इसलिए हमने एजेंसी से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। एजेंसी कैसे वाहनों का संचालन करेगी, यह ,सोचना उनका काम है- अरूणेंद्र चौहान, अपर सचिव, स्वास्थ्य[x]

निष्कर्ष- हम सभी जानते है कि हर प्रदेश में मरीजों के लिए एंबुलेंससेवा का होना कितना अनिवार्य होता है। वहीं जहां पर पहाड़ी प्रदेश के मरीजों के लिए 108 जैसी सरीकी सेवा किसी वरदान से कम नहीं होती है। जब से यह सेवा उत्तराखंड में दौडने लगी तब से उसका गौरवान्वित इतिहास रहा है, आपात स्थिति में तो इस सेवा ने मरीजों के लिए भगवान तुल्य कार्य किया है। लेकिन हाल ही में जीवीके कंपनी और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चला जाना बेहद चिन्तय विषय है। वहीं प्रदेश में शासन-प्रशासन और कर्मचारियों के आपसी मतभेद का आम जनता कब तक भुगतान करती रहेंगी, लगता है कि उत्तराखंड की डबल इंजन त्रिवेन्द्र सरकार, जीवीके कंपनी और कर्मचारियों के आपसी मतभेद इस सुविधा को कहीं आईसीयू में ना पहुंचा दे। जहां एक तरफ उत्तराखण्ड सरकार अतिमहत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के तहत पहाड़ के लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त बीमा कवर की आक्सीजन दे रही है वहीं आपातकालीन एबुलेंस 108 सेवा के पहिये थमने की नौबत किसकी हीवाहवाली से आई? हमनें इस शोध पत्र में जाना कि आपातकालीन प्रतिक्रिय 108 सेवा ने उत्तराखंड प्रदेश के लिए आक्सीजन का काम किया है, आकंडों पर नज़र डालने से पता चलता है कि पहाड़ी प्रदेश ने मौजूदा समय तक 108 सेवा ने आपात स्थिति में 12,84,482 बार सेवा दी, साथ ही 31477 लोगों के जीवन बचाने में कायम रहीं है। वहीं 13,877 महिला प्रसूताओं में सहायता करने का गौरव इस सेवा को हासिल है। उत्तराखंड सरीके प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुविधा को आम लोग की पहुंच तक ले जाना बहुत ही आवश्यक है, लोगों का मानना है कि इस तरह की आपातकालीन प्रतिक्रिया 108 सेवा मरीजों पर रोकथाम लगाना गलत होगा। सरकार को इस सेवा से जुड़े सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते अत्यंत तीव्र गति से हल करना चाहिए।

---

[i] जीवीके की आधिकारिक वेबसाइट से https://www.gvk.com/gvkfoundation/emri.aspx

[ii] http://hi.vikaspedia.in/health/108-90692a93e92491593e932940928-9

[iii] ईएमआरआई की आधिकारिक वेबसाइट से http://www.emri.in/

[iv] ईएमआरआई की आधिकारिक वेबसाइट से http://www.emri.in/

[v] Amy J Kesterton, John Cleland and Carine Ronsmans (2010). Institutional delivery in rural India: the relative importance of accessibility and economic status. Biomed Central. 6 June. Accessed 8 July 2014

[vi] Cash-strapped 108 ambulance service stops mid-way, Pioneeradmin, http://www.pioneeredge.in/cash-strapped-108-ambulance-service-stops-mid-way/ 09/01/2019

[vii] Uttarakhand Government to strengthen 108 emergency ambulance services, PNS https://www.dailypioneer.com/2017/state-editions/uttarakhand-government-to-strengthen-108-emergency-ambulance-services.html / 09/01/2019

[viii] सरकार 108 के नए 'करार' को तैयार, अमर उजाला, देहरादून https://www.amarujala.com/dehradun/108-ambulance-service-in-uttarakhand / 09/01/2019

[ix] '108' ambulance services disrupted across Uttarakhand, Shivani Azad | TNN https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/108-ambulance-services-disrupted-across-state/articleshow/66141556.cms/ 09/01/2019

[x] सरकार 108 के नए 'करार' को तैयार, अमर उजाला, देहरादून https://www.amarujala.com/dehradun/108-ambulance-service-in-uttarakhand / 09/01/2019

Reference:

1. Anirudh Krishna and Kripa Ananthpur (2013). Globalization, Distance and Disease: Spatial Health Disparities in Rural India. A study funded by 3ie. Accessed 5 July 2014.

2. Prakash, A Surya (2009). Governments That Work - I: Primary Health Care Finally Takes Off in the States. Available from http://www.vifindia.org/article/2009/april/Governments-That%20Work-IPrimary-Health-Care-Finally-Takes-Off-in-the-States. Accessed 5 July 2014.

3. Chakraborty Lekha, Yadawendra Singh and Jannet Farida Jacob (2012). Public Expenditure Benefit Incidence on Health: Selective Evidence from India. Working Paper No. 2012-111. December 2012. National Institute of Public Finance and Policy. New Delhi. Accessed 5 July 2014.

4. Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India and The World Bank in India (2011). Improving Road Safety: Tamil Nadu Road Sector Project. Innovations in Development, issue 5.

5. KPMG (2010). Health Care: Reaching out to the masses. Pan IIT Conclave 2010. Available from http://www.kpmg.com/IN/en/Pages/default.aspx. Accessed 5 July 2014.

6. Krishna, A. and D. Bajpai (2011). Lineal Spread and Radial Dissipation: Experiencing Growth in Rural

7. India, 1993-2005. Economic and Political Weekly, September 17, pp. 44-51.

8. Government of India (2013). Report of the Committee for evolving a composite development index of states.

9. Gupta Indirani (2009). Out of Pocket Expenditures and Poverty: Estimates from NSS 61st Round.